(ग) इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा इन कारखानों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०राजा रमन्ना) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में दो फैक्टरियां रंगीन पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण कार्य कर रही हैं। वर्ष 1989 के दौरान इनके उत्पादन की संख्या लगभग 5.3 लाख थी।

(ग) निम्नलिखित सुविधाएं, जो इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जे उद्योग को उपलब्ध हैं, इन दोनों फैक्टरियों को भी उपलब्ध करायी गई है :—

— इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा उद्योग को लाइसेंस मुक्त किया गया है।

— विदेशी सहयोग की अनुमति उदार रूप से दी गई है।

— इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा उद्योग को एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 22क के अन्तर्गत अनुमति लेने से छूट दी गई है।

— इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा के विनिर्माण के लिए आवश्यक अधिकांश उत्पादन सीमा शुल्क की रियायती दरों पर उपलब्ध है।

— औजार, सांचे, मोल्ड सीमा शुल्क की रियायती दरों पर उपलब्ध है।

— खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत भारी संख्या में पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जाती है।

— परियोजना के आयात के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं के मामले में सीमा शुल्क की रियायती दरें लागू होती हैं। आधुनिकीकरण/संतुलन के लिए आवश्यक भारी संख्या में पूंजीगत वस्तुओं के मामले में भी सीमा शुल्क की रियायती दरें लागू होती हैं।

Progress of Investigations in the kickbacks paid by AB Bofors

392. SHRI VIDUTHALAI VIRUMBI:
SHRI PASUMPON THA KIRUTTINAN:
SHRI V. GOPALSAMY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to Unstarred Question 1729 given in the Rajya Sabha on the 27th March, 1990 and state:

(a) what progress has been made so far after the CBI delivered the Letter Rogatory to Swedish authorities seeking their co-operation in the Bofors investigations; and

(b) whether any information has since been gathered by the CBI in Kickbacks?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. RAJA RAMANNA): (a) The Government of Sweden have still to respond to the Letter Rogatory which was given to the Swedish authorities on 2nd April, 1990.

(b) The collection of information during such investigations is continuing.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति

393. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले 6 महीनों के दौरान सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में प्रबन्ध निदेशकों, अध्यक्षों और अन्य उच्च पदाधिकारियों के पदों पर नयी नियुक्तियां की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन उपक्रमों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन उपक्रमों में इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्तियों के नाम उनकी अर्हता और अनुभव क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।